आफ द रिकार्ड--यशवीर कादियान

इक तू ही नहीं तन्हां-उल्फत में मेरी...

वित्त विभाग के अधिकारी-कर्मचारी विशेष ज्ञान के धनी-लैस होने के कारण सरकार चलाने वाले लोगों के लिए श्रद्धा का पात्र रहते हैं। वित्त विभाग का महत्व आदि अनंत काल से चला आ रहा है। चाणक्य ने भी वित्त प्रबंधन के महत्व पर काफी कुछ लिखा और बताया है। अपने हरियाणा में वित्त विभाग में एक से बढ कर एक ऊंचे कई अनुभवी खिलाड़ियों की फौज हैं। कई दफा तो विभाग के ये लोग एक साथ इतने ऊंचे और नीचे चले जाते हैं कि दोनों साइड से डर लगता है। वित्त विभाग के लोग भी क्या करें? इनके काम की प्रकृति ही ऐसी है कि इनको चाहे अनचाहे बाल की खाल उतारनी ही पड़ती है। वो भी तब जब इस सरकार

में बाल इतने उगे भी नहीं हैं कि खाल उतारी जा सके। हां, ये जरूर है कि जहां बाल उगे वहां खूब ही झाड़ उग आए हैं। जहां नहीं उगे हैं वहां कई बेचारे 24 घंटे बीज, पानी, खाद के जुगाड़ में लगे रहते हैं। मुंह उठाए आसमान को तकते रहते हैं। इस आस में कि वो सुबह कभी तो आएगी। कभी तो बदरा उनके आंगन में भी बरसेंगे। कभी तो बाल उगेंगे। सो मामला ये है कि हर सरकार में हर मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग अक्सर अपने आपको तुर्रम खां समझते हैं। और अगर ये न भी समझना चाहें तो भी अपना काम निकालने को आतुर चाटुकार लोग इनको आ आ कर समझा-बता देते हैं कि ये कुछ खास हैं। सीएम सैल के लोगों की गलतफहमी दूर करने या इनके अरमानों को जमीन सुंघाने के लिए सरकारों में वित्त विभाग हमेशा ही उपलब्ध रहता है। तत्पर रहता है। मुख्यमंत्री स्टाफ में चाव से आए एक सज्जन अपनी सरकारी सुविधाओं-भत्तों की मनमाफिक टर्मज एंड कंडीशन बनवाने के चाहवान हैं। मुख्यमंत्री स्तर

पर मंजूरी के बाद इन सज्जन की फाइल जब वित्त विभाग के यहां पहुंची तो वहां कई लोग इसको रिसीव करने के लिए अपने हथियार पैने करके तैयार बैठे थे। हमेशा की तरह। जब इस फाइल का अपने अंदाज में वहां मुआयना किया गया तो टर्मज एंड कंडीशन को रूल बुक के हिसाब से फिट नहीं पाया गया। सो उन्होंने अपने अंदाज में फाइल पर कलम चला दी। कई लोग ऐसा सोच-कह-मान-बता-जता-लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री की मंजूरी पर अड़गा अड़ा दिया। ये भी कि अगर मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग अपना भला ही नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर बाकी हरियाणा का कितना भला कर पाते होंगे? हालांकि वित्त विभाग में तो यूं फाइल डील करना रूटीन का काम है। वहां के लोग तो डयूटी कर रहे हैं। गुनाह थोड़े ही कर रहे हैं। अपनी आंख-नाक-कान के नीचे गलत नहीं करते। होने देते। उनका न किसी से द्वेष रहता न किसी से मोह। मैरिट पर फैसला करते हैं। बस कभी कभी डयूटी करने के मामले में ज्यादा गंभीर

हो जाते हैं। वित्त विभाग वालों की इन्हीं मनमोहक, मीठी,शातिर,कातिल,नटखट,पैनी,चुलबुली,सम्मोहित सी करती अदाओं-अंदाज के बारे में तो शहरयार ने बहुत पहले उमरावजान फिल्म में लोगों को कह दिया था... इक तू ही नहीं तन्हां, उल्फत में मेरी रूस्वा-इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं-इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं-इक सिर्फ हम ही मय को आंखों से पिलाते हैं-कहने को तो दुनिया में मयखाने हजारों हैं-इस शम्म-ऐ- फिरोजां को आंधी से डराते हो-इस शम्म-ऐ- फिरोजां के परवाने हजारों है।

परिश्रम

ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार में अपने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ही काम कर रहे हैं। विज को देख कर ऐसा लगता है कि बाकि मंत्री तो फौकट का वेतन ले रहे हैं। जींद में लोगों के कष्ट निवारण के लिए उपस्थित हुए विज ने वहां

एक एक्सीईन को कष्ट दे दिया। कष्ट निवारण कमेटी की मीटिंग के घटनास्थल पर बार बार बिजली आ जा कर रही थी। विज ने इस वारदात को गंभीरता से लिया। एक्शन ले लिया। मीटिंग तो अन्य मंत्री भी हरियाणा में लेते रहते हैं। क्या वहां बत्ती गुल होने का रिवाज नहीं हैं या फिर अपने विज साहब को ज्यादा परिश्रम की आदत है?

भूमिका

मुश्किल से मनोहर सरकार की गाड़ी पटरी पर आती है और सरकार के अपने लोग ही इसको पटरी से उतारने को व्याकुल रहते हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि चंडीगढ में बैठे दो कौड़ी के नेता और अफसर गुड़गांव के विकास में अड़चन पैदा कर रहे हैं। राव इंद्रजीत चूंकि गुड़गांव के सांसद हैं सो वो अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए चितिंत रहते हैं। ये राव साहब का पुराना अंदाज है। जैसे जैसे सरकार का वक्त गुजरने लगता है वो अपने लिए

पहले से माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। भूमिका बनाने में जुट जाते हैं। मोदी मंत्रीपरिषद में फेरबदल में राव का मंत्रालय भी बदला है। उनको शहरी विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। इसी मंत्रालय के अधीन देश में स्मार्ट सिटी बनाने का काम करता है। गुड़गांव को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल न किए जाने से राव इंद्रजीत खफा है। अब उनको मौका मिल गया है कि वो अपने मंत्रालय से तो गुड़गांव का कायाकल्प करवाएं। पिछली हुड्डा सरकार पर भी राव हाथ साफ करते रहते थे। दम हैं तो किसी दिन मोदी सरकार पर हाथ आजमाएं।

लौहपुरूष

पांच-सात दिन पहले की ही बात है। उचाना से भाजपा विधायक और केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता फरमा रही थी कि उनके पति के दरबार में बड़े बड़े मुख्यमंत्री हाजिरी लगाते हैं। संभवतः उनका आशय ये रहा

होगा कि ग्रामीण विकास,पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्रालय संभालने वाले बीरेंद्र सिंह के पास व्यापक काम है। अकेले ग्रामीण विकास मंत्रालय का ही करीब 90 हजार करोड़ रूपए का बजट है। अपने राज्यों के लिए ज्यादा फंड-स्कीम हासिल करने के लिए बीरेंद्र सिंह के यहां मुख्यमंत्री गुजारिश करते रहते हैं। हालांकि प्रेमलता ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो तथ्यों से अलग हो,लेकिन उनको इस बड़बोलेपन से बचना चाहिए था। अब जब मोदी कैबिनेट में फेरबदल हुआ तो बीरेंद्र सिंह के पर कतर दिए गए। उनके तीन बड़े मंत्रालय ले लिए गए और इस्पात मंत्रालय थमा दिया गया। इस्पात मंत्रालय के साथ खनन मंत्रालय भी जुड़ा होता था,लेकिन ये मंत्रालय बीरेंद्र सिंह को नहीं मिला। ये पीयूष गोयल को दे दिया गया। इस फेरबदल पर बीरेंद्र सिंह की पत्नी क्या कहेंगी? यही कि उनके पति के फौलादी व्यक्तित्व-इरादे देख कर ही फौलाद मंत्रालय दिया गया है।

वैसे कोई कुछ कहता रहे। बीरेंद्र सिंह हैं लौहपुरूष। वैसे नहीं जैसे सरदार पटेल थे। कुछ दूसरे टाइप के हैं ये।

अचानक

ये भाजपा सरकार में क्या हो रहा है? पहले यशपाल सिंघल को डीजीपी लगाया। अचानक। फिर उनको डीजीपी से हटाया। अचानक से। अब उनकी बेटी को महाधिवक्ता कार्यालय से हटा दिया गया है। अचानक।

पोस्ट नई-काम वही

पुलिस में कुछ समय पहले हुए फेरदबल में एक एडीजीपी स्तर के आईपीएस अधिकारी को महत्वपूर्ण पद हटा दिया गया। उनकी कार्यशैली को लेकर विधायकों और मंत्रियों में खासा रोष था। सबकी नजरों से बचाने और छुपाने के लिए ही उनको हटाने की नौबत आई। बताते हैं कि हट कर भी ये

साहब हटे नहीं है। अब भी ये कई काम वहीं करते हैं जो पुरानी पोस्ट पर रह कर करते थे। इन साहब के स्थान पर आए नए साहब कुछ नरम स्वभाव के हैं। सो ये भी उनकी जड़ नहीं खोद रहे। हां,अगर कोई ऊंचा खिलाड़ी आ जाता तो फिर इन एडीजीपी को दिक्कत हो जाती।